

MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

HASSANPUR (PALWAL)

NOTES

FOREIGN POLICY OF INDIA

MA-3RD SEM (POL.SCIENCE)

SYLLABUS

MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

POLITICAL SCIENCE

FOREIGN POLICY OF INDIA-I

M.A. 2nd Year (Semester-3) : Paper-5

PAPER CODE : 21POL23DC3

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

Theory : 80, Assignment : 20

Note : The question paper will be divided into five Units carrying equal marks i.e. 16 marks of such question. Each of first four units will contain two questions and the students shall be asked to attempt one question from each unit. Unit five shall contain eight short answer type questions without any internal choice and it shall be covering the entire syllabus. As such, all questions in unit five shall be compulsory internal choice and it shall be covering the entire syllabus. As such, all questions in unit five shall be compulsory.

Unit-I Meaning of Foreign Policy : History, Principles, Objectives and Determinants of India's Foreign Policy.

Unit-II (i) Formative Phase :

- (a) Legacies of the freedom struggle
- (b) Domestic background
- (c) Nehru's perspective, Critical analysis
- (d) International situation

(ii) Process of Foreign Policy making in India

Unit-III Non-alignment meaning, Features Bases and Role of India in the Non-alignment movement : Indian and third world.

Unit-IV India's Security Environment and India's Foreign Policy :

- (a) Domestic environment
- (b) Regional environment
- (c) International environment
- (d) India and United Nations (UN)

Unit-1

Foreign policy का हिंदी में अर्थ होता है "विदेश नीति"। यह एक देश द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और बाहरी देशों के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रणनीतियाँ और निर्णय होते हैं। विदेश नीति में एक देश अपनी कूटनीतिक, आर्थिक, और सुरक्षा संबंधी नीतियों को तय करता है, ताकि वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

विदेश नीति का इतिहास (History of Foreign Policy) का मतलब है किसी देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के क्षेत्र में किए गए निर्णयों और घटनाओं का इतिहास। हर देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, और वैश्विक प्रभाव के उद्देश्य से निर्धारित होती है। यह न केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में है, बल्कि इसमें उस देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, रक्षा, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की रणनीतियाँ भी शामिल होती हैं।

भारत की विदेश नीति का इतिहास

भारत की विदेश नीति का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक बहुत ही विविध और महत्वपूर्ण रहा है। यहां कुछ महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा की जा रही है:

- प्राचीन काल (Ancient Period):** प्राचीन भारतीय सभ्यताओं जैसे मोहनजोदड़ो और हड्डप्पा की सभ्यता के समय विदेश नीति का एक रूप था, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित था। चीन, मिस्त्र, और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे।
- मौर्य और गुप्त साम्राज्य (Maurya and Gupta Empires):** मौर्य साम्राज्य के समय, सम्राट अशोक ने विदेश नीति में अहिंसा और शांति के सिद्धांत को लागू किया। उनका उद्देश्य था कि भारत शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी ताकत को बढ़ाए और अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त साम्राज्य के समय, भारत का व्यापार, कला और संस्कृति दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया।
- मध्यकाल (Medieval Period):** मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न मुस्लिम साम्राज्यों का प्रभुत्व था। इन साम्राज्यों ने विदेश नीति में संघर्ष और कूटनीति का अधिक प्रयोग किया। दिल्ली सल्तनत और मुघल साम्राज्य ने विभिन्न देशों के साथ युद्ध और संधियाँ कीं।
- ब्रिटिश काल (British Colonial Period):** ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत की विदेश नीति ब्रिटेन के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के माध्यम से उपनिवेशों में अपने व्यापारिक और सामरिक हितों को बढ़ाया। भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की सामरिक और व्यापारिक योजनाओं के अनुसार थी।

5. **स्वतंत्रता के बाद (Post-Independence):** 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की विदेश नीति को महात्मा गांधी के आदर्शों और जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने "गांधीवादी अहिंसा" और "सार्वभौमिकता" को विदेश नीति का हिस्सा बनाया। नेहरू ने शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया और भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6. **समकालीन दौर (Contemporary Period):** 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत की विदेश नीति में बदलाव आया। व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता दी गई, और भारत ने पश्चिमी देशों, जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ, के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। साथ ही, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ भी भारत ने अपने रिश्तों को बढ़ाया।

21वीं सदी में, भारत की विदेश नीति में सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण, और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, भारत ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी भूमिका को भी मजबूत किया।

विदेश नीति के सिद्धांत (Principles of Foreign Policy) वे मूल विचार और दिशाएँ होती हैं, जिनके आधार पर एक देश अपनी विदेश नीति को तैयार करता है। ये सिद्धांत राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. गांधीवादी अहिंसा (Gandhian Non-Violence)

महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार, भारत की विदेश नीति अहिंसा और शांति पर आधारित रही है। गांधीजी का मानना था कि युद्ध और संघर्ष से कोई समस्या हल नहीं हो सकती, और हमें शांति, सह-अस्तित्व और सहकारिता के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए।

2. सार्वभौमिकता (Universalism)

भारत की विदेश नीति सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका मतलब है कि भारतीय नीति न केवल भारतीय हितों को ध्यान में रखती है, बल्कि दुनिया के सभी देशों के हितों का भी सम्मान करती है। भारत वैश्विक शांति, मानवाधिकार, और समानता के सिद्धांतों का पालन करता है।

3. गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement - NAM) के सिद्धांत के अनुसार, भारत ने किसी भी ब्लॉक (पश्चिमी या सोवियत) से जुड़ने से इनकार किया। भारत ने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेश नीति अपनाई, जो न तो किसी के पक्ष में थी और न ही विरोध में। यह सिद्धांत विशेष रूप से 1950 और 1960 के दशकों में महत्वपूर्ण था।

4. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Coexistence)

भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" है। इसका अर्थ है कि देशों को एक-दूसरे के अस्तित्व और उनके आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। यह सिद्धांत विशेष रूप से भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण रहा है।

5. समानता और न्याय (Equality and Justice)

भारत का यह सिद्धांत है कि सभी देशों को समान अधिकार मिलना चाहिए और वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेते समय न्याय का पालन किया जाना चाहिए। भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छोटे और विकासशील देशों के पक्ष में खड़ा रहा है और उनका समर्थन किया है।

6. विकसित देशों के साथ सहयोग (Cooperation with Developed Countries)

भारत की विदेश नीति में विकसित देशों के साथ सहयोग और साझेदारी को महत्वपूर्ण माना गया है। व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और ऊर्जा के क्षेत्र में इन देशों के साथ सहयोग भारत की विकास प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन चुका है।

7. सुरक्षा और रक्षा नीति (Security and Defense Policy)

भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा एक अहम स्थान रखते हैं। यह सिद्धांत भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। भारत ने अपने रक्षा बलों को मजबूत किया है और क्षेत्रीय शांति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

8. आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation)

भारत की विदेश नीति में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना भी एक प्रमुख सिद्धांत है। भारत ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements) और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

9. संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी (Active Participation in UN and International Institutions)

भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी है। भारत का उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा, और विकास के लिए इन संस्थाओं का मजबूत समर्थन करना है। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भी प्रयास किए हैं।

10. आत्मनिर्भरता (Self-Reliance)

भारत की विदेश नीति में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि भारत अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम हो, बजाय इसके कि वह दूसरे देशों पर निर्भर रहे। यह सिद्धांत खासकर 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों और स्वतंत्र कूटनीतिक पहल के समय महत्वपूर्ण था।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और निर्धारण (Objectives and Determinants of India's Foreign Policy) भारत की विदेश नीति के आधार पर कई प्रमुख उद्देश्य और कारक होते हैं, जो इसे दिशा और आकार प्रदान करते हैं। इन उद्देश्यों और निर्धारणों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, कूटनीतिक निर्णयों और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को प्रभावित करते हैं।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य (Objectives of India's Foreign Policy)

1. राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण (Protection of National Security)

भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण करना है। इसके तहत भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक उपायों को अपनाता है। यह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ सुरक्षा संबंधों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

2. आर्थिक विकास और समृद्धि (Economic Development and Prosperity)

विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए भारत व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देता है। यह वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है।

3. सार्वभौमिकता और शांति (Universalism and Peace)

भारत की विदेश नीति का उद्देश्य वैश्विक शांति, सौहार्द्द और सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने हमेशा शांति और संघर्ष के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का हल खोजने

का प्रयास किया है। गुटनिरपेक्षा आंदोलन (Non-Aligned Movement) और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति इसके उदाहरण हैं।

4. वैशिवक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाना (Enhancing Global Diplomatic Influence)

भारत का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दिशा में भी प्रयास किए हैं।

5. विकासशील देशों का समर्थन (Support for Developing Countries)

भारत की विदेश नीति विकासशील देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। भारत हमेशा से वैशिवक दक्षिण (Global South) के देशों के समर्थन में खड़ा रहा है और उनके लिए वैशिवक मंच पर आवाज उठाई है। इसके तहत विकासशील देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय सहायता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

6. प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा सुरक्षा (Natural Resources and Energy Security)

ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करना भी भारत के विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए भारत अपने ऊर्जा साझेदारों के साथ मजबूत सहयोग स्थापित करता है, जैसे कि मध्य-पूर्व देशों, रूस और अन्य ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण (Determinants of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख निर्धारण होते हैं। ये निर्धारण भारत के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक दृष्टिकोण और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होते हैं। प्रमुख निर्धारण इस प्रकार हैं:

1. भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)

भारत की भौगोलिक स्थिति उसके विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, जहां उसके पड़ोसी देशों के साथ जटिल राजनीतिक और सुरक्षा संबंध हैं। इसके अलावा, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है, जो वैशिवक व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ संघर्षों और विवादों के कारण, भारत की विदेश नीति में सुरक्षा संबंधों पर

विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए भारत अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने, कूटनीतिक गठबंधन बनाने, और आतंकवाद विरोधी उपायों को प्रोत्साहित करता है।

3. आर्थिक स्थिति (Economic Status)

भारत की आर्थिक स्थिति भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए भारत वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है और विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करता है। भारत के आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के कारण विदेश नीति में भी बदलाव आया है।

4. राजनीतिक दृष्टिकोण (Political Ideology)

भारतीय नेतृत्व की राजनीतिक विचारधारा और कूटनीतिक दृष्टिकोण भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, नेहरूवादी काल में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया, जबकि वर्तमान में भारत अपनी विदेश नीति में अधिक प्रौद्योगिकी और व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाता है।

5. संविधान और आंतरिक राजनीति (Constitution and Domestic Politics)

भारत का संविधान और उसकी आंतरिक राजनीतिक स्थिति भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। आंतरिक असंतोष, राजनीतिक स्थिरता, और सार्वजनिक राय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6. वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाएँ (Global and Regional Events)

वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाएँ भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और वैश्विक महामारी जैसे मुद्दे भारत की कूटनीति और निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

7. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू (Cultural and Historical Factors)

भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। भारत का गांधीवादी सिद्धांत, भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान, और ऐतिहासिक संबंध जैसे कारक विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Unit-2

स्वतंत्रता संग्राम की धरोहरें भारतीय समाज और राजनीति में गहरी पैठ बनाए हुए हैं। यह संघर्ष केवल ब्रिटिश सामाज्य से मुक्ति का प्रयास नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अस्मिता और स्वाभिमान के पुनर्निर्माण का प्रतीक भी था। स्वतंत्रता संग्राम की कुछ महत्वपूर्ण धरोहरें निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रवादी चेतना:** स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों में एक नई राष्ट्रवादी चेतना का जन्म दिया। इस संघर्ष ने भारतीयों को अपने अधिकारों और स्वाधीनता की महत्ता समझने के लिए प्रेरित किया। यह चेतना आज भी भारतीय समाज में गहरी है।
- संविधान और लोकतंत्र की नीव:** स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकतंत्र और गणराज्य की अवधारणा को मजबूती मिली। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान का लागू होना, स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी धरोहर है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान:** स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे नेता थे जिन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। आंबेडकर, गांधी, पं नेहरू, और अन्य नेताओं ने समाज में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया।
- सशस्त्र संघर्ष और अहिंसा का सिद्धांत:** स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र संघर्ष के साथ-साथ महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को भी प्रोत्साहित किया। यह सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति और आंतरिक संघर्षों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है।
- नारी सशक्तिकरण:** स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिला आंदोलनों ने अपनी जगह बनाई। रानी दुर्गावती, सुभद्राकुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
- स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनके विचार:** स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महान नेताओं ने भारतीय राजनीति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उनके विचारों और कार्यों ने भारतीय समाज को प्रेरणा दी और आज भी उनके विचारों का प्रभाव है।
- प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण:** गांधीजी के सत्याग्रह आंदोलन में, विशेषकर चिपको आंदोलन और पर्यावरण के संरक्षण की भावना उत्पन्न हुई थी। पर्यावरणीय जागरूकता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विचार स्वतंत्रता संग्राम के विचारों का एक हिस्सा रहे हैं।

स्वतंत्रता संग्राम की ये धरोहरें भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं और आज भी हमें अपनी संस्कृति, समाज और लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रेरणा देती हैं।

विदेश नीति की घरेलू पृष्ठभूमि (Domestic Background of Foreign Policy) का तात्पर्य उस देश की आंतरिक परिस्थितियों और समाजिक-राजनीतिक संदर्भ से है, जो उसकी विदेश नीति को आकार देती हैं। एक देश की घरेलू पृष्ठभूमि, जैसे उसकी राजनीतिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था, समाजिक संरचना, और सुरक्षा स्थिति, विदेश नीति को प्रभावित करती हैं और उसे दिशा प्रदान करती हैं।

यहां कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं, जो किसी देश की विदेश नीति की घरेलू पृष्ठभूमि को प्रभावित करते हैं:

1. राजनीतिक स्थिति:

किसी भी देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति विदेश नीति को प्रभावित करती है। यदि देश में राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष चल रहा हो, तो उसकी विदेश नीति को भी उस संकट या अस्थिरता से निपटने के लिए रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में है, तो उसकी विदेश नीति आमतौर पर नागरिकों के अधिकारों और वैश्विक मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होती है। वहीं, एक तानाशाही सरकार की विदेश नीति अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति की ओर केंद्रित हो सकती है।

2. आर्थिक स्थिति:

एक देश की आर्थिक स्थिति उसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समृद्ध और विकसित देश वैश्विक व्यापार, निवेश, और विकास कार्यों में अग्रणी हो सकता है, जबकि एक गरीब या विकासशील देश अपनी विदेश नीति को आर्थिक सहायता प्राप्त करने, संसाधन जुटाने और व्यापारिक रिश्ते सुधारने पर केंद्रित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वह अपने पड़ोसी देशों से व्यापारिक समझौतों या अंतर्राष्ट्रीय सहायता की ओर देख सकता है।

3. सामाजिक संरचना:

देश की सामाजिक संरचना, जैसे जाति, धर्म, और संस्कृति भी विदेश नीति पर असर डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक देश में बहुसंख्यक समुदाय का प्रभुत्व है, तो विदेश नीति में उस समुदाय की प्राथमिकताओं को महत्व मिल सकता है। साथ ही, किसी धार्मिक या सांस्कृतिक गठबंधन की भावना भी विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है।

4. सुरक्षा और सामरिक हित:

राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक जरूरतें भी किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश को बाहरी आक्रमण या आतंकवाद का खतरा महसूस होता है, तो उसकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा गठबंधनों और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना हो सकता है। इसके अलावा, सैन्य शक्ति बढ़ाने या सैन्य अनुबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं।

5. जनमत और सार्वजनिक राय:

किसी देश की जनसंख्या की सोच और विचार भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। अगर नागरिकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक निश्चित राय बनती है, तो सरकार उसे ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को निर्धारित करती है। जैसे, यदि देश की जनता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति चाहती है, तो सरकार भी कूटनीतिक प्रयासों में शांति और संवाद को प्राथमिकता दे सकती है।

6. संविधानिक और कानूनी ढांचा:

विदेश नीति के निर्माण में देश के संविधान और कानूनी ढांचे का भी बड़ा योगदान होता है। यदि देश में विदेश नीति के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं, तो सरकार उन्हीं के अनुरूप निर्णय लेती है। उदाहरण के तौर पर, किसी देश में यदि संविधान में यह प्रावधान हो कि विदेश नीति को संसद की मंजूरी से लागू किया जाएगा, तो इसका सीधा असर उस देश की विदेश नीति पर पड़ेगा।

7. नेताओं का दृष्टिकोण:

विदेश नीति को आकार देने में देश के नेताओं की व्यक्तिगत सोच और दृष्टिकोण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार, एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता के आधार पर विदेश नीति में बदलाव देखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ नेता अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में सक्रियता और विस्तार की नीति अपना सकते हैं, जबकि कुछ नेताओं का ध्यान देश की आंतरिक समस्याओं पर ज्यादा हो सकता है।

डित नेहरू के विदेश नीति दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु:

1. नॉन-आलाइंड मूवमेंट (गैर-आलाइंड आंदोलन):

नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति को नॉन-आलाइंड यानी "गैर-आलाइंड" आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित किया। उनका मानना था कि भारत को शीत युद्ध के दोनों प्रमुख गुटों (अमेरिका और सोवियत संघ) से बचते हुए, स्वतंत्र रूप से वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। वे चाहते थे कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए, किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा न बने और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करे।

2. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:

नेहरू जी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

इसका उद्देश्य युद्ध और हिंसा से बचना और संवाद एवं समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना था।

3. आत्मनिर्भरता (Self-reliance):

नेहरू जी का दृष्टिकोण यह था कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मामलों में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने विदेश नीति को इस तरह से विकसित किया कि भारत अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो, ताकि वह किसी भी वैश्विक दबाव का सामना कर सके। इसके तहत उन्होंने औद्योगिकीकरण और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया।

4. भारत का नेतृत्व:

पंडित नेहरू का मानना था कि भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने तीसरे विदेशों के बीच सहयोग और समर्थन के लिए एक मजबूत आवाज़ उठाई, ताकि वे औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हो सकें। नेहरू जी ने यूएनओ (संयुक्त राष्ट्र संघ) के मंच का उपयोग कर कई देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया और वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के लिए आवाज़ उठाई।

5. मूल्य और नीतिकता:

नेहरू जी ने विदेश नीति में मूल्य और नीतिकता को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपराएँ हमें विश्व में शांति, समानता और सहयोग की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने वैश्विक संबंधों में अहिंसा, सच्चाई और न्याय की नीतियों को बढ़ावा दिया।

6. संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ:

नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि यह संस्थाएँ वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं और भारत को इन संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को संघर्षों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में देखा।

7. चीन के साथ संबंध:

पंडित नेहरू ने चीन के साथ अपने संबंधों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत अपनाया था। हालांकि, 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद उनकी नीति में बदलाव आया, लेकिन पहले वे चीन को एक महत्वपूर्ण मित्र मानते थे और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की विकालत करते थे।

8. नारीवाद और मानवाधिकार:

नेहरू जी ने विदेश नीति में मानवाधिकार और नारीवाद को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि भारत को उन देशों के साथ संबंध बढ़ाने चाहिए जो समानता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation) का तात्पर्य वैश्विक स्तर पर देशों के बीच के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और सैन्य संबंधों से है। यह स्थिति विभिन्न देशों के आपसी संबंधों, वैश्विक शक्तियों के बीच संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संगठन और अन्य वैश्विक घटनाओं के आधार पर आकार लेती है।

आज के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें राजनीतिक संघर्ष, व्यापारिक संबंध, पर्यावरणीय मुद्दे, सुरक्षा चिंताएँ, और वैश्विक महामारी जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

नीचे कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करते हैं:

1. वैश्विक शक्तियों का संतुलन:

आज के अंतर्राष्ट्रीय परिवृश्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, और रूस जैसी प्रमुख शक्तियाँ वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये शक्तियाँ न केवल सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावी हैं, बल्कि उनकी विदेश नीतियाँ और कूटनीतिक कदम भी वैश्विक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

- अमेरिका:** अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित है। अमेरिका के राजनीतिक फैसले वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यापार युद्ध, जलवायु परिवर्तन समझौतों से बाहर निकलना, और वैश्विक सुरक्षा को लेकर नीतियाँ।
- चीन:** चीन तेजी से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, और बेल्ट एंड रोड (BRI) जैसी वैश्विक परियोजनाएँ चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाती हैं।
- रूस:** रूस भी एक प्रमुख सैन्य और ऊर्जा आपूर्ति शक्ति है। रूस के कदम, विशेषकर यूरोप और मध्य एशिया में, वैश्विक कूटनीति पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण स्वरूप, यूक्रेन संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय और वैश्विक स्थिति को प्रभावित किया है।

2. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका:

अंतरराष्ट्रीय स्थिति में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे:

- **संयुक्त राष्ट्र (UN):** यह वैश्विक शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में अक्सर विभाजन और संघर्ष होते हैं, जो उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO):** यह वैश्विक व्यापार के नियमों को स्थापित करने और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
- **ग्लोबल क्लाइमेट चेंज़:** जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गई है, और इसके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है। पेरिस जलवायु समझौता इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है।

3. आर्थिक वैश्वीकरण:

आजकल वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। हालांकि, वैश्वीकरण ने कुछ देशों के लिए आर्थिक विकास के अवसर खोले हैं, वहीं यह असमानता, बेरोजगारी और स्थानीय उद्योगों पर दबाव भी डालता है। वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कारक वैश्विक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

4. जंगी संघर्ष और आतंकवाद:

दुनिया में कई जंगें और संघर्ष जारी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन संघर्षों के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं और मानवीय संकट उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए:

- **सीरिया युद्ध:** यह संघर्ष वैश्विक कूटनीति में विभाजन और तनाव का कारण बना है।
- **अफगानिस्तान संकट:** तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद वैश्विक सुरक्षा चिंताएँ बढ़ी हैं।
- **आतंकवाद:** आतंकवादी संगठनों जैसे आईएसआईएस और अल-कायदा का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करता है।

5. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है, जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है, बल्कि देशों के बीच टकराव और विवाद भी उत्पन्न करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है, और पेरिस जलवायु समझौते जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

6. कोविड-19 महामारी:

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्थिति को गहरे तरीके से प्रभावित किया है। इस महामारी ने न केवल मानव जीवन को नुकसान पहुँचाया, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी अस्थिरता पैदा की। देशों के बीच चिकित्सा आपूर्ति और वैक्सीनेशन पर प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे वैश्विक सहयोग और राजनीति पर असर पड़ा।

7. प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा:

प्रौद्योगिकी, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया मोड़ दिया है। देशों के बीच साइबर हमले और तकनीकी युद्ध बढ़ रहे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित करते हैं।

भारत में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया (Process of Foreign Policy Making in India) एक जटिल और कई स्तरों पर काम करने वाली प्रक्रिया है, जो देश के आंतरिक और बाहरी हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, और राजनीतिक नेताओं के बीच विचार-विमर्श, निर्णय-निर्माण और कार्यान्वयन के चरणों से गुजरती है।

भारत की विदेश नीति को आकार देने के लिए कई प्रमुख तत्व और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं:

1. प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल:

भारत में विदेश नीति बनाने का मुख्य जिम्मा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल पर होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, विदेश नीति के प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री विदेश नीति के लिए नीतिगत दिशा निर्धारित करते हैं और इसे लागू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विदेश नीति से संबंधित प्रमुख निर्णयों को मंत्रिमंडल की बैठक में भी मंजूरी मिलती है।

2. विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs):

विदेश मंत्रालय भारत सरकार का मुख्य अंग है जो विदेश नीति को लागू करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों में देश की स्थिति को संभालने का कार्य करता है। विदेश मंत्रालय में प्रमुख अधिकारी **विदेश मंत्री** होते हैं, जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा मामलों में विदेशी देशों से संबंधित कार्यों को संभालते हैं।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA):

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का पद भारत की सुरक्षा और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NSA प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मामलों में सलाह देता है। NSA की भूमिका, विशेष रूप से सुरक्षा, आतंकवाट, और सैन्य रणनीतियों से जुड़ी नीति बनाने में होती है।

4. रक्षा मंत्रालय:

रक्षा मंत्रालय का विदेश नीति निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर यदि किसी मामले में सैन्य या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो रक्षा मंत्रालय का सहयोग प्राप्त किया जाता है। कई बार, भारत की विदेश नीति में सुरक्षा मामलों को प्रमुखता दी जाती है, जैसे चीन, पाकिस्तान, और अन्य पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में।

5. भारतीय संसद:

भारतीय संसद का विदेश नीति निर्माण में अप्रत्यक्ष योगदान होता है। संसद में विदेश नीति पर चर्चा होती है और सांसद इसे लेकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। हालांकि विदेश नीति के प्रमुख निर्णय मंत्रीमंडल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन संसद इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है और कभी-कभी विदेश नीति पर नए दिशा-निर्देश भी देती है।

6. राजनीतिक दल और विचारधाराएँ:

राजनीतिक दल और उनके विचारधाराएँ भी भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डालते हैं। विभिन्न दलों के दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताएँ विदेश नीति में बदलाव ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक समय पर कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण गैर-आलाइंड आंदोलन पर था, जबकि अन्य दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया है।

7. वैशिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ:

विदेश नीति का निर्माण अक्सर वैशिक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, यदि वैशिक संकट, जैसे कि युद्ध, आर्थिक मंदी, या पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं, तो भारत की विदेश नीति को इन घटनाओं के अनुसार तैयार किया जाता है। इसके अलावा, देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक तनाव, जैसे कि चीन या पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, भी विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8. गोपनीयता और कूटनीतिक चर्चा:

विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया में गोपनीयता और कूटनीतिक चर्चाएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। अधिकतर निर्णय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले गुप्त रूप से कूटनीतिक संवाद और चर्चा के बाद किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में, सरकार विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह लेती है और कई बार रणनीतिक दृष्टिकोण से विचार-विमर्श करती है।

9. सार्वजनिक राय और मीडिया:

विदेश नीति निर्माण में सार्वजनिक राय और मीडिया की भूमिका भी बढ़ी है। खासकर वैश्विक घटनाओं और विदेश नीति के बड़े फैसलों पर जनता की प्रतिक्रिया को सरकार गंभीरता से लेती है। मीडिया और सार्वजनिक बहसों से विदेश नीति को लेकर जागरूकता और आलोचना उत्पन्न होती है, जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

10. विचारधारा और राष्ट्रीय हित:

विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू **राष्ट्रीय हित** होता है। नीति निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारत के दीर्घकालिक हितों की रक्षा हो, चाहे वह आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक संबंध, पर्यावरण या मानवाधिकार से संबंधित हो। इसके साथ ही, भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांत भी विदेश नीति के आधार होते हैं।

Unit-3

गैर-आलाइंड (Non-Alignment) का मतलब है कि कोई देश किसी सैन्य गठबंधन या राजनीतिक गुट के साथ न जुड़कर स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति तय करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत, एक देश शीत युद्ध (Cold War) के दौरान दो प्रमुख महाशक्तियों—अमेरिका और सोवियत संघ—के साथ सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं होता।

भारत ने इस नीति को अपनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम करें, बिना किसी बाहरी दबाव के। यह नीति नेहरूवाद से प्रेरित थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था।

गैर-आलाइंड आंदोलन के मुख्य सिद्धांत:

- स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता:** अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लेना और किसी भी बड़े सैन्य गुट से जुड़ने से बचना।
- सामूहिक सुरक्षा:** शांति और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।

3. गुटनिरपेक्षता: शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों प्रमुख गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र कूटनीति बनाना।

भारत ने गैर-आलाइंड आंदोलन (NAM) की शुरुआत 1961 में की थी, जिसमें भारत के अलावा कई विकासशील देशों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य था वैश्विक शांति बनाए रखना, आंतरिक संघर्षों को हल करना और संघर्षों के समाधान के लिए स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना।

गैर-आलाइंड आंदोलन (Non-Alignment Movement - NAM), जो 1961 में प्रारंभ हुआ, एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान देशों को किसी भी महाशक्ति के सैन्य और राजनीतिक गुटों से बचाकर स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाने के लिए प्रेरित करना था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गैर-आलाइंड आंदोलन के प्रमुख विशेषताएँ (Features of Non-Alignment Movement):

1. **गुटनिरपेक्षता:**

- गैर-आलाइंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था किसी भी सैन्य गुट (अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गुट) से अलग रहना। इसका मतलब यह था कि सदस्य देश स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति तय करेंगे, बिना किसी बाहरी दबाव के।

2. **शांति और सुरक्षा की नीति:**

- गैर-आलाइंड आंदोलन शांति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संघर्षों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देता था। इसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना और युद्ध की संभावना को कम करना था।

3. **समानता और सहयोग:**

- इस आंदोलन का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच समानता, सहयोग और आपसी सहायता को बढ़ावा देना था। इसमें प्रमुख रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश शामिल थे।

4. **स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता:**

- आंदोलन के सदस्य देशों का मानना था कि उन्हें अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों में पूरी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए, ताकि वे अपनी विकास यात्रा में बाधित न हों।

5. **शीत युद्ध से बचाव:**

- गैर-आलाइंड आंदोलन शीत युद्ध के दौरान पैदा होने वाली दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव से बचने का एक प्रयास था। यह आंदोलन किसी एक गुट के पक्ष में न होकर तीसरे दुनिया के देशों को एक मंच प्रदान करता था।

गैर-आलाइंड आंदोलन के सिद्धांत (Bases of Non-Alignment Movement):

1. राष्ट्रीय स्वतंत्रता:

- प्रत्येक देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी स्वतंत्रता का अधिकार है। देशों को किसी भी बाहरी दबाव या सैन्य गठबंधन में न फँसा कर अपनी विदेश नीति स्वायत्त रूप से निर्धारित करनी चाहिए।

2. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:

- यह सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि सभी देशों को एक-दूसरे के साथ शांति से रहना चाहिए और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

3. किसी भी युद्ध से बचना:

- गैर-आलाइंड आंदोलन ने युद्ध की निंदा की और संघर्षों का समाधान कूटनीति और संवाद से निकालने की कोशिश की।

4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- गैर-आलाइंड देशों ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र (UN) में समान रूप से कार्य करने पर जोर दिया।

5. धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण:

- आंदोलन में भाग लेने वाले देशों ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध धर्म, जाति या भाषा से ऊपर हों।

भारत की भूमिका (India's Role in Non-Alignment Movement):

भारत ने गैर-आलाइंड आंदोलन में एक प्रमुख और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने इस आंदोलन की दिशा को आकार दिया और उसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया।

1. नेहरू जी का नेतृत्व:

- पंडित नेहरू ने गैर-आलाइंड आंदोलन के सिद्धांतों को स्थापित किया और उन्हें लागू करने के लिए देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित किया। उनका यह मानना था कि भारत को किसी भी सैन्य गुट में नहीं शामिल होना चाहिए और शांति, सह-अस्तित्व और सहयोग की नीति अपनानी चाहिए।

2. गैर-आलाइंड आंदोलन की नीति:

- 1955 में बांदंगुंग सम्मेलन के बाद, भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में पहले गैर-आलाइंड सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। यह सम्मेलन गैर-आलाइंड आंदोलन का औपचारिक आरंभ था, और भारत ने इसके आधार को मजबूत किया।

3. दूसरी दुनिया के देशों के साथ सहयोग:

- भारत ने तीसरी दुनिया के देशों के हितों को अपने विदेश नीति में सर्वोपरि माना। उसने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज़ को वैश्विक स्तर पर उठाया।

4. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज़:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा की और शांति, समानता, और संघर्षों के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर अपना पक्ष रखा।

5. कूटनीतिक पहल:

- भारत ने शीत युद्ध के दौरान अपनी कूटनीति को संतुलित बनाए रखते हुए दोनों महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। भारत ने कभी भी किसी एक पक्ष को समर्थन नहीं दिया, बल्कि हमेशा तटस्थ रहने की नीति अपनाई।

तीसरी दुनिया और गैर-आलाइंड आंदोलन:

गैर-आलाइंड आंदोलन के तहत मुख्य रूप से तीसरी दुनिया के देशों ने अपनी भागीदारी दिखाई। तीसरी दुनिया के देशों में वे देश शामिल थे, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे और अब स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनका विकास बाकी देशों की तुलना में काफी पीछे था। इन देशों का उद्देश्य था:

1. **औपनिवेशिकता से मुक्ति:** तीसरी दुनिया के देशों ने अपने आप को औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त कराने के लिए गैर-आलाइंड आंदोलन का हिस्सा बनकर संघर्ष किया।
2. **आर्थिक और सामाजिक विकास:** इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की।
3. **अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिरता:** इन देशों ने संयुक्त रूप से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई और अपनी आवाज़ को प्रभावी बनाने की कोशिश की।

भारत का सुरक्षा पर्यावरण (India's Security Environment) और भारत की विदेश नीति का घरेलू वातावरण (Domestic Environment of India's Foreign Policy)

Unit-4

1. भारत का सुरक्षा पर्यावरण (India's Security Environment):

भारत का सुरक्षा पर्यावरण बहुत ही जटिल और विविध है, जिसमें कई प्रकार की चुनौतियाँ और खतरे शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामरिक, कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कई रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं।

1. पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद:

- भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही कश्मीर का मुद्दा एक प्रमुख विवाद रहा है, जो दोनों देशों के बीच युद्ध और संघर्ष का कारण बन चुका है। पाकिस्तान का आतंकी गतिविधियों में समर्थन और सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष भारत के लिए सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

2. चीन के साथ सीमा विवाद:

- भारत और चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सीमा विवाद रहा है। 1962 का युद्ध इसके उदाहरण के रूप में देखा जाता है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और रणनीतिक गतिविधियाँ, जैसे "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) और दक्षिण एशिया में प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, भारत की सुरक्षा पर दबाव डालती हैं।

3. आतंकवाद:

- भारत विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत में आतंकवादी हमले और घुसपैठ की घटनाएँ लगातार होती रहती हैं।

4. सैन्य संघर्षों और क्षेत्रीय अस्थिरता:

- अफगानिस्तान में हाल की राजनीतिक अस्थिरता और मध्य एशिया में चल रहे संघर्ष, भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में होने वाली राजनीतिक घटनाएँ भी भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर डालती हैं।

5. परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक:

- भारत के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसके पड़ोसी देशों के पास भी परमाणु शक्ति का अस्तित्व है, जैसे पाकिस्तान और चीन। इसके चलते परमाणु युद्ध की संभावना और सामरिक संतुलन का मुद्दा भी अहम बन जाता है।

भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ:

- "सामरिक बफर जोन" की रक्षा: भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है, ताकि सामरिक तनाव को कम किया जा सके।
- "प्रोएक्टिव डिफेंस": भारत ने अपनी रक्षा नीति में सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाना और सीमा पर मजबूत गश्त को प्राथमिकता दी है।
- "पूर्वी समुद्र नीति": भारत ने भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाया है ताकि वह समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
- "सैन्य गठबंधन": भारत क्वाड (QUAD) जैसे सैन्य गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं।

2. भारत की विदेश नीति का घरेलू वातावरण (Domestic Environment of India's Foreign Policy):

भारत की विदेश नीति पर उसके घरेलू वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ घरेलू राजनीति, आर्थिक परिस्थितियाँ, समाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा, और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ मिलकर भारत की विदेश नीति को आकार देती हैं।

1. राजनीतिक स्थिरता और सरकार की विचारधारा:

- भारत की सरकार की विचारधारा और नेतृत्व विदेश नीति के निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे यदि भारत में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है, तो उसकी विदेश नीति में गैर-आलाइंड आंदोलन और गुटनिरपेक्षता की दिशा को प्रमुखता मिलती है, जबकि भा.ज.पा. (भारतीय जनता पार्टी) के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव को अधिक महत्व दिया जाता है।

2. आर्थिक स्थिति और विकास:

- भारत की आर्थिक स्थिति और विकास लक्ष्य उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की विदेश नीति में व्यापार समझौतों, विदेशी निवेश और आर्थिक सहयोग को प्रमुखता दी जाती है।
- मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएँ विदेश नीति के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यह नीतियाँ भारत के वैश्विक व्यापार और रणनीतिक रिश्तों में सुधार करने के लिए काम करती हैं।

3. सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण:

- भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारत की संविधानिक धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मानवाधिकार की विचारधारा विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
- प्रवासियों (NRI) के मुद्दे, भारतीय संस्कृति का प्रचार और हिंदू धर्म की विचारधारा, खासकर पारंपरिक नीतियों को प्रोत्साहित करने के मामले में भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।

4. आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद:

- आतंकी हमलों और सुरक्षा समस्याओं के मद्देनजर भारत को अपनी विदेश नीति में समायोजन करना पड़ता है। जैसे, कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान से आतंकवाद और चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सुरक्षा नीति और विदेश नीति को प्रभावित करते हैं।

5. लोकप्रिय राय और मीडिया:

- भारत में सार्वजनिक राय और मीडिया भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जनता की प्रतिक्रिया और मीडिया की रिपोर्टिंग, खासकर आतंकवाद, सीमा विवाद और वैश्विक मामलों में भारत के रुख को आकार देती है।

भारत की विदेश नीति के घरेलू प्रभाव:

- **सुरक्षा और कूटनीतिक निर्णय:** घरेलू सुरक्षा चिंताएँ जैसे पाकिस्तान के साथ तनाव या चीन के साथ सीमा संघर्ष भारत की विदेश नीति में प्रमुख बदलावों का कारण बनती हैं।
- **व्यापारिक रणनीतियाँ:** घरेलू आर्थिक विकास के लिए आर्थिक संबंधों और व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देना भारत की प्राथमिकता बन जाती है।
- **राजनीतिक विचारधारा:** सरकार की विचारधारा के अनुसार भारत की विदेश नीति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, नेहरूवादी गैर-आलाइंड नीति से लेकर मोदी सरकार की आत्मनिर्भरता और वैश्विक ताकत बनने की दिशा तक के परिवर्तन।
- **विदेश नीति का क्षेत्रीय पर्यावरण (Regional Environment of Foreign Policy)** उस भौगोलिक या राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में होता है, जिसमें एक देश अपनी विदेश नीति को आकार देता है और लागू करता है। यह पर्यावरण उन क्षेत्रीय ताकतों, घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में घटित होती हैं। इसमें देशों के आपसी संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, और संघर्ष, साथ ही वैश्विक शक्ति संतुलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रभाव शामिल होते हैं।

विदेश नीति के क्षेत्रीय पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भौगोलिक स्थिति:

- एक देश की भौगोलिक स्थिति उसके विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एशिया, यूरोप, या अफ्रीका में स्थित देशों की प्राथमिकताएँ और संघर्ष अलग हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने आस-पास के देशों और क्षेत्रों के साथ अलग प्रकार के संबंध बनाए रखते हैं।

2. क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव:

- हर क्षेत्र में कुछ प्रमुख ताकतें होती हैं, जो उस क्षेत्र की राजनीति और आर्थिक दिशा तय करती हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण एशिया में भारत एक प्रमुख ताकत है, तो यूरोप में जर्मनी और फ्रांस महत्वपूर्ण हैं।

3. संघर्ष और सहयोग:

- क्षेत्रीय संघर्ष, जैसे सीमा विवाद, जातीय या धार्मिक मतभेद, या अन्य विवाद, एक देश की विदेश नीति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत, क्षेत्रीय सहयोग (जैसे एशियाई देशों के बीच व्यापारिक समझौते) भी विदेश नीति की दिशा को आकार देता है।

4. सार्वजनिक और निजी कूटनीति:

- क्षेत्रीय पर्यावरण देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करता है, जो उन्हें साझा हितों (जैसे सुरक्षा, व्यापार, और संसाधन) और व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए आपसी समझौते बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

5. क्षेत्रीय संगठन और संस्थाएँ:

- क्षेत्रीय संगठन जैसे ASEAN (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ), SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन), EU (यूरोपीय संघ) आदि विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इन संगठनों के सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, और सुरक्षा सहयोग का बड़ा योगदान होता है।

6. वैश्विक ताकतों का प्रभाव:

- विश्व शक्तियाँ, जैसे अमेरिका, चीन, रूस आदि, भी क्षेत्रीय पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के हितों के तहत है, तो वहाँ की विदेश नीति इन शक्तियों के साथ तालमेल रखने के लिए प्रभावित हो सकती है।

7. आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

- क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार समझौते (जैसे RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership) से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

8. सुरक्षा और रक्षा प्राथमिकताएँ:

- क्षेत्रीय सुरक्षा परिवृत्ति, जैसे क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन या आतंकवाद और सीमा विवाद, देशों की विदेश नीति के सुरक्षा पहलू को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति, या दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव, दोनों ही देशों की विदेश नीति पर असर डालते हैं।

उदाहरण:

- भारत की विदेश नीति का क्षेत्रीय पर्यावरण:** भारत की विदेश नीति पर दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। भारत को पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांगलादेश और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना होता है, जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं।

इस प्रकार, विदेशी नीति का क्षेत्रीय पर्यावरण उन विभिन्न कारकों को शामिल करता है, जो एक देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और उसे क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण (International Environment) का मतलब उस वैश्विक संदर्भ से है जिसमें एक देश अपनी विदेश नीति, कूटनीति, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करता है। यह पर्यावरण वैश्विक शक्तियों, अंतरराष्ट्रीय संगठन, वैश्विक समस्याओं और प्रवृत्तियों, तथा विभिन्न देशों के आपसी रिश्तों से प्रभावित होता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण न केवल देशों के आपसी संबंधों को आकार देता है, बल्कि वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी प्रभावित करता है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वैश्विक शक्तियाँ (Global Powers):

- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण में वैश्विक शक्तियाँ जैसे अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत जैसी प्रमुख ताकतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन देशों के राजनीतिक, आर्थिक, और सैन्य प्रभाव से वैश्विक निर्णयों और घटनाओं का दिशा-निर्देशन होता है।

2. अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organizations):

- अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), नाटो (NATO) आदि का वैश्विक नीति और सहयोग पर गहरा असर पड़ता है। ये संगठन देशों के बीच संवाद, सहमति, और सहयोग बढ़ाने के लिए बने हैं और वैश्विक मुद्दों जैसे सुरक्षा, व्यापार, मानवाधिकार, और स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं।

3. वैश्विक आर्थिक स्थिति (Global Economy):

- वैश्विक आर्थिक स्थिति, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वित्तीय बाजार, और विकासशील देशों की स्थिति, देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, वैश्विक मंदी या आर्थिक संकट का प्रभाव किसी भी देश की आर्थिक नीति पर पड़ सकता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में बदलाव आते हैं।

4. वैश्विक संघर्ष और सुरक्षा (Global Conflicts and Security):

- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण में युद्ध, आतंकवाद, और सैन्य संघर्ष जैसे मुद्दे वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, सीरिया युद्ध, अफगानिस्तान संघर्ष, यूक्रेन संकट, और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे क्षेत्रीय संघर्षों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। वैश्विक शक्ति संघर्ष और सैन्य गठबंधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

5. संशोधनात्मक और विकासात्मक मुद्दे (Reform and Development Issues):

- वैश्विक स्तर पर देशों को सामूहिक रूप से विभिन्न वैश्विक मुद्दों का समाधान करना होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य संकट (जैसे कोरोना महामारी),

और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इन मुद्दों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

6. विकासशील देशों की स्थिति (Status of Developing Countries):

- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण में विकासशील देशों की स्थिति और उनकी समस्याएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं। वैश्विक शक्तियाँ और अंतरराष्ट्रीय संगठन अक्सर इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएँ शुरू करते हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वार्ता (International Diplomacy and Negotiation):

- देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों, वार्ताओं और समझौतों का वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, पेरिस जलवायु समझौता और आयरन क्यूबा संधि जैसी कूटनीतिक पहलें अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण का हिस्सा हैं। देशों के बीच राजनयिक रिश्तों और संधियों का गठन अंतरराष्ट्रीय नीति को प्रभावित करता है।

8. सांस्कृतिक आदान-प्रदान (Cultural Exchange):

- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण केवल राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी प्रभावित होता है। संस्कृतिक संवाद, विदेशी शिक्षा, और सामाजिक आदान-प्रदान देशों के रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी बढ़ाते हैं। यह "मुल्टीपोलर" दुनिया के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9. वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय संकट (Global Climate and Environmental Crisis):

- जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ, और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय संकटों का समाधान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना होता है। वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों को लागू करने के लिए देशों के बीच सहयोग जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता वैश्विक प्रयासों का प्रतीक है।

उदाहरण:

- भारत का अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण:** भारत की विदेश नीति पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण का बड़ा असर पड़ता है, जैसे भारत का यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा, भारत-चीन रिश्ते,

भारत-उ.स. संबंध, और **भारत-रूस** जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी। साथ ही, भारत की जलवायु नीति और विकासशील देशों के समूह (G77) के साथ उसके रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक बहुत ही जटिल और विविधतापूर्ण अवधारणा है, जिसमें विभिन्न वैश्विक ताकतों, संघर्षों, सहयोगों और साझा समस्याओं का समावेश होता है। यह पर्यावरण देशों की विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। **भारत और संयुक्त राष्ट्र (India and United Nations)** के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत एक प्रमुख सदस्य देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और मानवाधिकारों का संरक्षण करना है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर योगदान दिया है। आइए देखें भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच रिश्तों के कुछ प्रमुख पहलुओं को:

1. संयुक्त राष्ट्र में भारत का सदस्यता (India's Membership in the UN):

- भारत ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद से संगठन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत को यूएन का सदस्य बनने में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था।
- भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट की है, विशेष रूप से शांति, न्याय और समावेशिता के मामले में।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council):

- भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा:** भारत ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता की मांग की है। भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह अधिक प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक और न्यायसंगत बने। भारत विशेष रूप से एशिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और आर्थिक महाशक्ति होने के कारण सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार मानता है।
- भारत का योगदान:** भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहा है और सुरक्षा परिषद में कई बार चर्चा में रहा है, विशेष रूप से आतंकवाद, सीमा विवाद और शांति स्थिरता के मामलों में।

3. मानवाधिकार और विकास (Human Rights and Development):

- **भारत का मानवाधिकारों के प्रति रुख़:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में अपने योगदान के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए हमेशा आवाज उठाई है। भारत ने विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों, गरीबी उन्मूलन और समानता के मुद्दों पर जोर दिया है।
- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP):** भारत, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का सक्रिय सदस्य है, जो विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करता है। भारत ने कई वैश्विक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी की है।

4. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UN Peacekeeping Missions):

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह विश्व में सबसे बड़े शांति सैनिकों (peacekeepers) को भेजने वाले देशों में से एक है। भारतीय सैनिकों ने कई देशों में शांति स्थापना के लिए काम किया है, जैसे कांगो, लाइबेरिया, श्रीलंका, और दक्षिणी सूडान।
- भारत का यह योगदान संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के प्रति इसके मजबूत समर्थन को दर्शाता है।

5. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण (Climate Change and Environment):

- भारत ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत सक्रिय रूप से काम किया है। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) का समर्थन किया है और इसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में अपने योगदान की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के क्षेत्रों में कई पहल की हैं।

6. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly):

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने विचारों को प्रकट किया है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। भारत का कहना है कि वैश्विक निर्णयों में विकासशील देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
- भारत ने हमेशा महासभा के मंच से वैश्विक आतंकवाद, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामूहिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है।

7. सामूहिक सुरक्षा और आतंकवाद (Collective Security and Terrorism):

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है और यह मानता है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक और समग्र कानूनी ढांचा बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं।
- भारत ने हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से अधिक सक्रिय और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

8. भारत और संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी (India's Partnership with the UN):

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों के साथ सहयोग किया है, जैसे **UNICEF, UNESCO, WHO, और FAO** आदि, ताकि वैश्विक कल्याण और विकास में योगदान किया जा सके।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, और सतत विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।

9. भारत का योगदान और भूमिका:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अपनी भूमिका निभाई है, जैसे **UNHCR** (United Nations High Commissioner for Refugees), **UNEP** (United Nations Environment Programme), और **WHO** (World Health Organization) में योगदान किया है।
- भारत ने वैश्विक स्तर पर गरीब देशों के लिए विकासात्मक सहायता, खाद्य सुरक्षा, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी समर्थन प्रदान किया है।